Dattopant Thengadi Foundation

दिनांक : 15/04/2021

गिग इकोनॉमी

"गिग इकोनॉमी" ने वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अपनी एकजगहबनाई है, हालांकि, यह एकनई अवधारणा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म-आधारित कंपनियों के आगमनऔरसफलता ने इसे एकसामान्य शब्द बना दिया है। भारत में भी हमने शहरी औरग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों, निर्माण क्षेत्र औरकईअन्य कईक्षेत्रों में गिग श्रमिकों के झलकको देखा है। वर्तमान में बसएकबदलाव हुआ है की व्यक्तिगत पहचान औरजानकारी के जगहप्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्म अबकाम दिलाने लगे है । विश्व स्तर पर 20 करोड़ से अधिक लोग गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं जिसमें विकासशील देश विकसित देशों की तुलना में अधिक भागीदारी दिखा रहे हैं। इसके अलावा, अधिकांश नौकरियां निम्न-आयप्रकार की हैं जैसे कि डिलीवरी, ड्राईवर, देखभाल, आदि। 2017 में अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि वैश्विक गिग श्रमिकों का 24 प्रतिशत भारत से था। विभिन्न रिपोर्टों, सर्वेक्षणों औरअध्ययनों ने अलमअलगतरीकों से "गिग कार्य या श्रमिक " को परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन मोटे तौर पर हम इसे अस्थायी औरऐसे काम के रूप में परिभाषित करसकते हैं, जिसके लिए भुगतान कार्य आधार या समयके आधार पर किया जाता है औरइसमें कोई भी औपचारिक अनुबंध हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है ।

हाल ही में, कंसल्टेंसी फर्म बीसीजी एक रिपोर्ट लेकर आई है जिसमें कहा गया है कि गिग इकॉनमी भारत में गैर-कृषि क्षेत्रों में 9 करोड़ नौकरियों तक का सृजन कर सकती है, जिससे भविष्य में जीडीपी में 1.25 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें यह भी कहा गया है कि लंबी अवधि के लिए गिग इकॉनमी से 250 अरब अमरीकी डालर से अधिक का लेनदेन हो सकता है। लघु-से-मध्यम अवधि में, कुशल, अर्ध-कुशल और साझा सेवाओं की भूमिकाओं में लगभग 2.4 करोड़ नौकरियों को गिग इकॉनमी के माध्यम से सृजनित किया जा सकता है, जिसमें लगभग 30 लाख साझा सेवाओं की भूमिका और लगभग 85 लाख नौकरियां घरेलू मांग को पूरा करती हैं। यह रिपोर्ट 7 करोड़ नौकरियों के निर्माता के रूप में निर्माण, विनिर्माण, परिवहन और रसद और व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रों की पहचान करते हुए यह कहता है कि छोटे व्यवसाय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबी अवधि के दौरान लगभग 3.5 करोड़ कुशल और अर्ध-कुशल

नौकरियां होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुविधा प्रबंधन, परिवहन, और लेखा जैसी साझा सेवाओं की भूमिकाओं के माध्यम से 50 लाख नौकरियों को प्राप्त किया जा सकता है, और 1.2 करोड़ नौकरियां घरेलू मांग से उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि 3.7 करोड़ अकुशल नौकरियां अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से आ सकते हैं। गिग अर्थव्यवस्था अगले दो-तीन वर्षों में लगभग 10 लाख नई नौकरियां पैदा कर सकती है। इसमें कहा गया है कि गिग श्रमिक आम तौर पर कम आयु के होते हैं, दिन में कम घंटे काम करते हैं, अपेक्षाकृत कम शिक्षित होते हैं, और अधिकतर घरेलू आय में सहायक के रूप में काम करते हैं।

पिछले महीने गिग श्रमिकों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। एक ओर जहाँ ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय के साथ एक ग्राहक की हाथापाई का मामला चर्चित रहा वही दूसरी ओर एक उबर ड्राइवर की एक और घटना भी सामने आई। उबर ड्राइवर नेरी श्रीकांत तिरुपति से वापस आने के बाद उबर के साथ कैब सेवा जारी नहीं रख सके क्योंकि है कि उबर ऐप ने उन्हें लॉग इन करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि बाल मुंडवाने के बाद यह उनके बदले हुए स्वरूप को पहचानने में विफल रहा। उबेर का कहना है कि ड्राइवर ने कंपनी के सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ऐप तक पहुंच खो दी, न कि इसलिए कि उसका रूप बदल गया। कंपनी ने यह जानकारी साझा नहीं की है कि किन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया। तेलंगाना गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स यूनियन ने इस मुद्दे को उठाया और केंद्र और राज्य सरकारों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश कर रही है जिसमें उबर और ओला जैसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें हैदराबाद स्थित उबेर ड्राइवर की विवादास्पद बर्खास्तगी और गिग कामगारों के सामने आने वाले अन्य तकनीकी मुद्दे शामिल थे। । एसोसिएशन ने देश भर के लोगों को भी आमंत्रित किया की वो फर्मों के प्लेटफार्मों पर तकनीकी मुद्दों से प्रभावित होने के अपनी कहानियों को साझा करे और आंदोलन का हिस्सा बने।

गिग अर्थव्यवस्था में, ऐप -आधारित व्यवसाय खुद को "बाज़ार" या "प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों" और श्रमिकों को "साझेदार" या "स्व-नियोजित व्यक्ति" के रूप में नामकरण करते हैं। इन फर्मों में कोई औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंध नहीं होता । इन शब्दावली में कई लाभ हैं, यह फर्मों को ऐसे विधायी ढांचे से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है जो सेवाओं के लिए श्रम सुरक्षा और राज्य-विनियमित दरों को सुनिश्चित करता है (जैसे सरकार द्वारा निर्धारित टैक्सी किराए), दूसरा, यह उन्हें प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कार और मोटरबाइक जैसी संपत्ति के स्वामित्व और रखरखाव की लागतों को स्थानांतरित करने की भी सुविधा देता है। मुख्य आर्थिक लाभ व्यापारिक संगठनों को जाता है जो अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं और श्रम लागत को कम कर सकते हैं। श्रमिक संगठन की दया पर हैं कि उन्हें काम पर रखा जाए | इससे भी बदतर उनका रोज़गार इसपर भी निर्भर करता है की ग्राहक उन्हें खराब रेटिंग दे सकते हैं। हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा कोड "प्लेटफार्म" और "गिग" श्रमिकों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभों की संभावना प्रदान करता है। हालाँकि, इस बात की अविलम्ब जरुरत है कि सरकारों को नियामक ढाँचों का विकास करना चाहिए जो प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के अधिकारों, विवादों

और शिकायतों के समाधान के लिए स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था बनाये और प्लेटफार्मों को श्रमिकों की आय सुरक्षा के लिए जवाबदेह बनाये हैं और श्रमिकों को उनके डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करे।

प्रकाशन:

1) Democracy, Capitalism, Labour Movement: In Quest of Decent Work: https://www.suruchiprakashan.com/democracy-capitalism-labour-movement

2) Decent Wage : It's not Just About Workers : https://www.suruchiprakashan.com/decent-wage

3) Industy 4.0 and the Future of Work(er) : https://www.suruchiprakashan.com/industry 4-0-and-the-future-of-work-er

---